Faridabad Plot Built Properties in all Sectors
SYNDICATE
ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11, Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288
Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक
नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES
(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa
24, Hours Service
Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 23 अंक 17 शुक्रवार, फरीदाबाद, 16-31 जुलाई, 2010 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 1 रुपया

हरियाणा पुलिस न सही

जम्मू पुलिस ने धर दबोचा मनमोहन

फ़रीदाबाद (म.मो.) अपने आप को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राजनैतिक सलाहाकार बताकर ठग्गी मारने वाले जिस मनमोहन सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ए-115, फतह नगर, नई दिल्ली को, लिखित शिकायत मिलने के बावजूद भी यहां की पुलिस ने पकड़ने की जरूरत नहीं समझी उसे जम्मू पुलिस ने केवल संदेह के आधार पर अपनी कुशलता से पकड़ कर हवालात में बंद कर दिया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मनमोहन सिंह ने पुलिस एवं सुरक्षा की तथाकथित चाक चौबंद व्यवस्था में सेंधमारी करके तथा पुलिस महकमे को बेवकूफ़ बनाकर अपने लिए जम्मू पुलिस की एस्कार्ट/पायलेट लगवा ली। इतना ही नहीं पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन ने इसके बहकावे में आकर 3 दिन तक इसकी व इसके साथ चलने वाली 3 महिलाओं व 2 गार्डों की भी खूब आवभगत की। इन्हें वैष्णो देवी के वीआईपी दर्शन तो करवाए सो करवाए साथ में मंदिर के वीआईपी गेस्ट हाऊस में ठहरने की भी बेहतरीन व्यवस्था की। लेकिन शीघ्र ही संदेह होने पर जम्मू पुलिस द्वारा नई दिल्ली से पड़ताल करने पर सारी पोल पट्टी खुल गई तो जनाब को वीआईपी गेस्ट हाऊस से सीधे हवालात में बंद कर दिया। इसी ठग मनमोहन सिंह से जनवरी 2009 में इस संवाददाता का भी पाला पड़ा था। संवाददाता ने स्वयं 13 जनवरी को इसके साथ दिल्ली-यूपी बॉर्डर से मेरठ तक का सफ़र तय किया था। उस दिन पहली बार इस ठग का जलवा देखा। करीब 5 कारों का काफ़िला लेकर चलने वाले इस ठग को पायलेट करने के लिए पहले तो गाजियाबाद पुलिस की गाड़ी तैयार खड़ी मिली। मेरठ ज़िले की सीमा शुरू होते ही गाज़ियाबाद की गाड़ी हट गई और मेरठ पुलिस की जीप जो पहले से तैयार खड़ी थी आगे आगे सायरन बजाती चल पड़ी।

मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में ले जाकर भी उस जीप ने इस ठग को नहीं छोड़ा बल्कि आगामी कार्यक्रम के लिए वहीं तैनात रही। वहां उस दिन सिखों का कोई धार्मिक कार्यक्रम था, जिसमें थोड़ी देर बाद वहां के आईजी गुरबचन लाल भी इस ठग के बुलावे पर आ पहुंचे। कार्यक्रम के अंत में सभी के साथ आईजी ने भी पंगत में बैठकर लंगर खाया। इसके बाद यह ठग आईजी की कोठी पर पहुंचा जहां उन्होंने इस ठग के साथ चल रहे लगभग 15-20 लोगों का चाय, काफ़ी व मिठाई आदि से स्वागत किया, इसके बाद यह ठग वहां से ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश की कोठी पर पहुंचा। इन सभी कार्यक्रमों के दौरान मेरठ पुलिस की जीप इस ठग को पायलेट करती रही और इसकी दिल्ली वापसी के दौरान इसे गाज़ियाबाद ज़िले की सीमा तक लाकर छोड़ा जहां से वहां की पुलिस ने इसे पायलेट किया।

इसी तरह का नाटक इस ठग ने 31 जनवरी 2009 को अपनी, दिल्ली से वृंदावन-मथुरा यात्रा के दौरान दिखाया। अजरौंदा चौक से यह संवाददाता इसके साथ लगा तो फ़रीदाबाद ज़िले की एक पुलिस जिप्सी इस ठग को पायलट कर रही थी। पलवल ज़िले की सीमा शुरू होते ही वहां पहले से तैयार खड़ी जिप्सी ने अपनी ड्यूटी संभाल ली। यूपी सीमा पर वहां की 2 पुलिस जीपों ने (एक आगे व एक पीछे) इस ठग के काफ़िले को अपनी सुरक्षा में ले लिया। वृंदावन के अनेकों मंदिरों के दर्शनों के बाद यह ठग अपने पूरे तामझाम के साथ मथुरा के ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह के निवास पर पहुंच गया। जज साहब ने इस ठग के साथ आए 15-20 लोगों का तरह-तरह की मिठाईयों व चाय, कॉफ़ी आदि से भरपूर स्वागत किया।

- शेष पेज 2 पर

पीएमओ में भी काली भेडें हैं

पुलिस को शिकायत करने के अलावा सूचना के अधिकार कानून के तहत 10.3.2009 प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इस मनमोहन के कारनामे बताते हुए पूछा गया था कि कौन है यह मनमोहन और इसे पुलिस सुरक्षा किस आधार पर मुहैय्या कराई जाती है?

पीएमओ के जनसूचना अधिकारी ने पोस्टल ऑर्डर सहित पत्र वापिस करते हुए कोई भी सूचना देने से इंकार कर दिया तो इसकी शिकायत केन्द्रीय सूचना आयुक्त से की गई। इसके बावजूद भी वहां से कोई ढंग का जवाब नहीं मिला। इससे सिद्ध होता है कि इस ठग ने वहां भी कोई न कोई काली भेड़ पटा रखी है।

सरकार ने फरीदाबाद गुड़गांव सड़क रिलायंस को बेच खाई

फरीदाबाद (म.मो.) फरीदाबाद-गुड़गांव रोड को रिलायंस कंपनी द्वारा 780 करोड़ रुपये खर्च कर फोर लेन का बनाया जा रहा है। यह ठेका प्राप्त करने के लिए रिलायंस ने बिड्स की शर्तों के अनुसार सरकार को 150 करोड़, 80 लाख रुपये भी दिये थे। ठेका प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेताओं को कितना चढ़ावा चढ़ाया होगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। रिलायंस कंपनी फरीदाबाद-गुड़गांव रोड को फोर लेन का बनाने के बाद अगले 15 वर्षों तक इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूलेगी। यानी सारे टैक्स सरकार को अदा कर चलने वाले वाहनों से एक प्राइवेट कंपनी को लूटने की खुली छूट दी जायेगी। अभी तक इस मार्ग को फोर लेन करने का कार्य इसलिए गति नहीं पकड़ पा रहा था, क्योंकि मार्ग में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग की अनापत्ति नहीं प्राप्त हुई थी। पर अब वन विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है, इसलिए अब काम रफ़्तार पकड़ेगा।

रिलायंस कंपनी ने मार्ग को फोर लेन करने के लिये जो खर्चा बताया है, वह प्रति किलोमीटर लगभग 26 करोड़ रुपये आ रहा है। इतना ज़्यादा खर्चा किसी हाल में नहीं आ सकता। यह खुली लूट है।

उल्लेखनीय है कि रिलायंस को सिर्फ़ 30 किलोमीटर मार्ग को फोर लेन करने का कार्य करना है। इस पर 780 करोड़ रुपये खर्च होने की बात किसी भी तरह समझ में नहीं आती। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि एक किलोमीटर रेलवे ट्रैक डालने पर 3 करोड़ रुपये का खर्चा आता है। फरीदाबाद-गुड़गांव के बीच 50 किलोमीटर रेलवे ट्रैक डलवाने पर कुल खर्च डेढ़ सौ करोड़ रुपये का आयेगा। कहां डेढ़ सौ करोड़ और कहां 780 करोड़? अगर सरकार लोगों को वास्तव में ही सुविधा मुहैया कराना चाहती तो वह वैकल्पिक रेल मार्ग भी बनवा सकती है। इससे लोगों को आवागमन की नई एवं सस्ती सुविधा भी मिल जाती और प्रदूषण की भी कोई समस्या नहीं रहती, जो सड़क यातायात बढ़ने पर होती है। पर सरकार का उद्देश्य लोगों को वास्तव में सुविधा प्राप्त कराना हो तब तो वह ऐसा करे।

उसका उद्देश्य तो सुविधा प्रदान करने के नाम पर लोगों की जेब काट कर अपनी जेब भरना है। इसके साथ ही, सरकार प्राइवेट कंपनियों को लोगों को लूटने का ठेका दे रही है। रिलायंस कंपनी ने मार्ग को फोर लेन करने के लिये जो खर्चा बताया है, वह प्रति किलोमीटर लगभग 26 करोड़ रुपये आ रहा है, इतना ज़्यादा खर्चा किसी हाल में नहीं आ सकता। यह खुली लूट है। इसके अलावा अगले 15 सालों तक वाहनों से टोल टैक्स वसूल कर यह कंपनी न जाने कितने हज़ार करोड़ का मुनाफ़ा कमायेगी। पाठक समझ सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियों को लूट की ऐसी छूट देने वाली सरकार जो अपने आप को जनहितैषी कहती है, जनहितैषी है या जनविरोधी?

अयोग्य लोग ‘चलायेंगे’ हिसार पावर प्लांट

हिसार (म.मो.) करीब 8000 करोड़ की लागत (भूमि सहित) से बना खेदड़ पावर प्लांट अति शीघ्र हरियाणा सरकार की संस्था एचपीजीसीएल (हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड) के सुपुर्द होने जा रहा है। इसको चलाने के लिए हरियाणा सरकार ने तकरीबन 200 छोटे-बड़े इंजीनियर व तकनीशियन अभी हाल ही में भर्ती किये हैं। इसके अतिरिक्त 200 अन्य लोग विभिन्न प्लांटों एवं विभागों के लिए भी चुने गये हैं।

विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस काम के लिए पहले आईआईटी के एक विशेषज्ञ पैनल को नियुक्त किया गया था, जिसने योग्यता एवं श्रेष्ठता के आधार पर 400 लोगों को चुना था। परंतु योग्यता पर आधारित यह चुनाव सरकार को पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें रोहतक से एक भी व्यक्ति नहीं चुना जा सका था और हरियाणा से भी मात्र तीन लोग चुने गये थे। अधिकांश लोग अन्य राज्यों से चुने गये थे। इसी बात को ले कर उक्त चुनाव सूची रद्द कर दी गई और दोबारा से नियुक्ति सूची तैयार कराई गई।

इस बार यह काम किसी विशेषज्ञ पैनल की बजाय हरियाणा सरकार के अपने पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराया गया। कहने की जरूरत नहीं कि इस कमीशन का काम उम्मीदवार की योग्यता की बजाय उसकी राजनीतिक पहुंच तथा मोटी जेब देखना होता है। इस कमीशन द्वारा चयनित सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे कर प्लांट चलाने का काम सौंप दिया गया है। अब ये लाग कैसा प्लांट चला पायेंगे, समझ पाना कठिन नहीं है। किसी हद तक यह बात ठीक है कि नौकरियां देते समय

कहने की जरूरत नहीं कि इस कमीशन का काम उम्मीदवार की योग्यता की बजाय उसकी राजनीतिक पहुंच तथा मोटी जेब देखना होता है। इस कमीशन द्वारा चयनित सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे कर प्लांट चलाने का काम सौंप दिया गया है। अब ये लाग कैसा प्लांट चला पायेंगे, समझ पाना कठिन नहीं है।

सरकार को स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन किस हद तक? क्या जनता के खून-पसीने से लगी 8000 करोड़ की पूंजी को गर्क करने की हद तक भी यह प्राथमिकता दी जानी चाहिए? नहीं, कदापि नहीं। यदि सरकार वास्तव में ही अपने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना चाहती है तो क्यों नहीं उन लोगों के शैक्षणिक, बौद्धिक तथा तकनीकी स्तर को ऊंचा उठाती? लेकिन यह स्तर तो तभी ऊंचा उठ सकता है जब राज्य शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, जबकि शिक्षा का स्तर एवं गुणवत्ता कहीं भी सरकार के एजेंडे पर नहीं है। सरकारी स्कूलों व कालेजों की दुर्दशा का विस्तृत विवरण ‘मज़दूर मोर्चा’ के विभिन्न अंकों में कई बार प्रकाशित किया जा चुका है। सरकारी स्कूलों व कालेजों के पद कई-कई बरसों से खाली पड़े हैं। जो स्टाफ़ पदासीन भी है, उसे पढ़ाई की अपेक्षा अन्य कामों - चुनाव, जनगणना, प्लस पोलियो आदि - में जोत दिया जाता है। ऐसे में जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो पास होने के लिए नकल का सहारा लेंगे। सारी हकीकत से परिचित अध्यापकगण भी ऐसे में नकल मारने से छात्रों को रोकना जरूरी नहीं समझते, बल्कि इस काम में उनको सहयोग ही करते हैं। जाहिर है, जब बिना पढ़े बच्चे नकल मार कर पास होंगे तो वे किस काम के होंगे?

इसी देश में केरल भी एक राज्य है जहां शिक्षा का स्तर एवं गुणवत्ता सर्वोत्तम है। इसी के चलते वहां के लोगों को न केवल देश में, बल्कि दुनिया के किसी भी भाग में नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी विधायक, सांसद या मंत्री की सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी योग्यता ही उनकी सिफ़ारिश करती है। लेकिन यह बात हरियाणा के धूर्त राजनेता कभी समझना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनकी प्राथमिकता जनहित की बजाय सदैव अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति रहा है।